

चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वैश्वीकरण क्यों?

साभार : फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(18 सितंबर, 2017)

अनिल.के. कानूनगो
(प्रोफेसर, लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

एक समय था जब वैश्वीकरण से प्राप्त होने वाला लाभ सदेह के घेरे में रहता था और पश्चिमी देशों से वैश्वीकरण प्रतिस्थापन में प्रतीत होता था, लेकिन अब चीन-आधारित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) वैश्वीकरण के उदय का एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभर रहा है।

बीआरआई, चीन के राष्ट्र को पुनर्जीवित करने के लिए शी जिनपिंग द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा 'चाइना ड्रीम' का हिस्सा है, जो एक दोहरी परियोजना है। यह ग्रेट यूरोपीय महाद्वीप को ओवरलैंड रेलवे से, राजमार्गों, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ने और दक्षिण पूर्व एशिया और यहां तक कि अफ्रीका के साथ बंदरगाहों और अन्य समुद्री संपर्कों के माध्यम से चीन को जोड़ने वाली एक बेल्ट है। सामूहिक रूप से, इसे 'वन बेल्ट, वन रोड (ओबीओआर)' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे आम तौर पर बीआरआई के रूप में जाना जाता है।

देखा जाये तो बीआरआई उस समय आई है, जब क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाग तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही गंभीर संघर्ष की संभावना के साथ विविध राष्ट्रवाद अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। आर्थिक वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार एक समय इतना बांधनीय प्रतीत होता था कि कुछ ही लोग इसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते थे। फिर भी इस तरह के लाभों के बारे में अब आम सहमति कम है।

बीआरआई का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि चीन के अविकसित इलाके और जंगलगे बेल्ट में वृद्धि के साथ इसे बढ़ावा देना है और चीन में असमानताओं को कम करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2017 में, शी जिनपिंग, इसमें उपस्थित होने वाले पहलं चीनी राष्ट्रपति है, ने सर्वसम्मति से भूमंडलीकरण का समर्थन किया और संरक्षणवाद का विरोध किया।

2014 के बाद के दौरान, चीनी सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू सिल्क रोड फंड और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की स्थापना की, जो कि बीआरआई में शामिल व्यापार और अन्य आर्थिक सहयोग का समर्थन करेंगे। लगभग उसी समय, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बनाने की पहल को दक्षिण एशिया में एक बड़ा विकास माना जाता था ताकि चीन को इस क्षेत्र में पर्याप्त पहुंच मिल सके। इस तरह की पहुंच के माध्यम से, चीन मध्य एशिया और अन्य जगहों पर अपने आर्थिक परिश्रम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

मई 2017 में, बीजिंग में बेल्ट और रोड फोरम प्रायोजित करने के लिए शी ने पहल की थी। जिसमें 30 से अधिक प्रमुख संगठन और कई राष्ट्रों के प्रमुख जैसे रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तचिप एर्दोगान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऐसी बैठक का उद्देश्य केवल अंतरराष्ट्रीय समर्थन और मान्यता पर कब्जा करने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सरकारी प्राथमिकता के रूप में बीआरआई को वैध बनाना था।

इन सभी घटनाक्रमों में, एक देश जो निश्चित रूप से बीआरआई के बारे में उत्साही नहीं दिखा वह भारत है, क्योंकि यह पाकिस्तान और रूस के साथ चीन के गहरे होते संबंधों के सन्दर्भ में चित्तित था। जिसे मई में इस मंच पर एक भी भारतीय प्रतिनिधि के मौजूद नहीं होने के उद्धारण से समझा जा सकता है। जून में भारतीय सैनिकों की अगुआई में चीन को भूटान में सड़क बनाने से रोकना इस संबंध को और बिगड़ दिया था, हालांकि अगस्त में जाकर इसका समाधान निकल आया। कई अन्य देशों के साथ, भारत ग्वादर की पाकिस्तान के गहरे पानी के बंदरगाह तक पहुंचने के रणनीतिक प्रभावों के बारे में परेशान है, जो चीन और उसके जियांगियांग प्रांत फारसी खाड़ी में खुलता है।

कुछ मामलों में, भारत और चीन सहयोग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत-पाकिस्तान के समीकरण ने इसे हमेशा कमज़ोर बनाया है। ब्रिक्स देशों के उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार कारक हो सकता है, लेकिन चीन और भारत के बीच लंबी अवधि से व्याप्त शत्रुता और शत्रुता का निरंतर सहयोग इसे कठिन बना देता है।

हालांकि सरकारें बीआरआई पर अधिकतर इच्छुक हैं, इसे आर्थिक विस्तार और समृद्धि के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, बहुत सामान्य लोग कम आश्वस्त हैं। मध्य एशिया में चीन की छवि मिश्रित है और कुछ चीन के आर्थिक विस्तार को अपरिहार्य लेकिन अपरिहार्य मानते हैं। वे इस तथ्य से नाराज हैं कि चीनी कंपनियां उनके साथ अपने स्वयं के श्रमिक भी लाती हैं, इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार पाने का मौका दूर हो जाता है। पश्चिम में भी राय विभाजित है। जबकि कई पर्यवेक्षक बीआरआई में लाभ और विकास के अवसर देखते हैं, तो



कई परियोजना व्यवहार्यता और वास्तविकता पर संदेह करते हैं। संदेहवादी विचार इसमें शामिल देशों के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से यह सक्षम हैं या नहीं, को दर्शाता है। कई पर्यवेक्षक चीन के मकसद पर संदेह करते हैं, यह मध्य एशियाई देशों और कुछ अफ्रीकी देशों पर चीन की पारंपरिक शक्ति को हासिल करने के लिए एक भूखंड के रूप में गिना जाता है।

यह कहना बहुत जल्दी होगी कि बीआरआई कम समय में सफल हो पायेगा या नहीं या कितना सफल हो सकता है। लेकिन चीनी दृढ़ता और दृढ़ता को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस परियोजना को लेकर बहुत गंभीर है। भूमंडलीकरण के पीछे हटने की स्थिति में, चीन बीआरआई के माध्यम से वैश्वीकरण के अपने जनादेश को आगे बढ़ाएगा। सभी संभावनाओं में, अगले कुछ दशकों में बीआरआई का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है और चीन के वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव का प्रमुख चालक बन सकता है।

बेल्ट और रोड

इस नीति का उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है। दरअसल, चीन विकासशील पूर्वी एशिया के आर्थिक केन्द्रों को विकसित यूरोपीय आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ना चाहता है। यहाँ 'बेल्ट' से तात्पर्य सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट से है जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है-

- चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग।
- चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्यसागर से जोड़ने वाला मार्ग।
- चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर से जोड़ने वाला मार्ग।

'रोड' से तात्पर्य 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड से है जिसका निर्माण दक्षिण चीन सागर व हिन्द महासागर के माध्यम से चीन के तट से यूरोप में व्यापार करने तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन के तट से दक्षिण प्रशांत तक व्यापार करने के लिये किया गया है।

महत्वपूर्ण?

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बेल्ट और रोड फोरम में विभिन देशों के 30 प्रमुख तथा 100 मंत्रीस्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। 'वन बेल्ट वन रोड' नीति का उद्देश्य चीन के घरेलू विकास को बढ़ावा देना है जिसमें हाल के वर्षों में गिरावट आई है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि 'वन बेल्ट वन रोड' पहल चीन की आर्थिक कूटनीति का खाका है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चीन स्वयं को अकेला महसूस करता है क्योंकि वह जी-7 में शामिल नहीं है और केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित है। उनका मानना है कि अपने आर्थिक विस्तार को जारी रखने के लिये चीन को एक नीति की आवश्यकता थी और 'वन बेल्ट वन रोड' पहल ने उसकी इस मंशा को बखूबी पूरा किया है।

चीन को क्या लाभ?

- इस वर्ष चीन ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लक्ष्य को घटाकर 6.5% पर सीमित कर दिया है जोकि विगत 25 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर है। वैश्विक रूप से चीन को अपनी आर्थिक सफलता को बरकरार रखने के लिये विकास के नए मॉडल की आवश्यकता है। 'वन बेल्ट वन रोड' पहल से चीन में बढ़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक सुधार होगा तथा इससे जुड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी टिकाऊ बनी रहेगी।
- 'वन बेल्ट वन रोड' के दो रूप हैं- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के पश्चात अमेरिका की नीति में आया बदलाव और पश्चिम में संरक्षणवादी नजरिये के उदय के कारण बाजार सिकुड़ रहे हैं जबकि बढ़ते श्रमिक मूल्यों, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक, वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण चीन में होने वाले निवेश में कमी आई है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि

मध्यम वर्ग की धीमी प्रगति से चीन के उपभोग स्तर में भी गिरावट आई है।

- इसके अतिरिक्त, 'वन बेल्ट वन रोड' पहल ने पश्चिम के विकसित बाजारों से एशिया के विकासशील देशों की ओर एक संक्रमण को दर्शाया है, इससे चीन के विकास की नीति में भी परिवर्तन हुआ है। यह अपने विकसित पूर्वी तट पर स्थित प्रान्तों की बजाय मध्य और पश्चिम चीन के प्रान्तों पर अधिक ध्यान दे रहा है।

क्रियान्वयन?

- मूलतः 'वन बेल्ट वन रोड' के लिये चीन के पूर्वी भाग को विकसित बनाने की आवश्यकता होगी ताकि यह अमेरिका और अन्य विकसित देशों से व्यापार कर सके, जबकि इसके मध्य और पश्चिमी प्रांत (जिनकी विकास दर कम है) एशिया के विकासशील देशों से व्यापार करें।
- हालांकि 'वन बेल्ट वन रोड' के मार्ग में एक सबसे बड़ा अवरोध यह है कि वर्तमान में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापार को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक अवसंरचना का अभाव है।
- चीन इसके इच्छुक देशों के साथ कार्य करने की अपेक्षा कर रहा है तथा उनके अवसंरचनात्मक निर्माण और तकनीकी व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान दे रहा है। 'वन बेल्ट वन रोड' के लिये अंतर्राष्ट्रीय मार्गों और एशिया के सभी उपक्षेत्रों तथा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले अवसंरचनात्मक नेटवर्क की आवश्यकता होगी।

आवश्यकता?

- माना जा रहा है है सिल्क रोड के चारों-ओर कई देशों ने अभी तक एक बाजारी अर्थव्यवस्था प्रणाली को स्थापित नहीं किया है तथा उनके घरेलू बाजारों को भी विनियमन और अवसंरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।
- सिल्क रोड से लगे हुए देशों के रेलवे, राजमार्ग और पाइपलाइन क्षेत्र में भी सुधार होना आवश्यक है क्योंकि परिवहन सुविधा अत्यावश्यक है। 'वन बेल्ट वन रोड' के साथ जुड़ने से चीन के अनुभवों, अवसंरचना निर्माण और कनेक्टिविटी तक पहुँच बनाना काफी आसान होगा।
- चीन में ऐसी कई अवसंरचना कंपनियाँ हैं जो इन देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। इसके माध्यम से चीन अनेक विकासशील देशों के लिये भी लाभकारी सिद्ध होगा।

चीन ने तीन नए अवसंरचना कोषों के लिये लगभग 100 बिलियन डॉलर का फंड देने की प्रतिक्रिया जाहिर की है-

- मध्य एशिया (जिसे 'सिल्क रोड कोष' कहा गया है) के लिये 40 बिलियन डॉलर का फंड।
- नए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के लिये 50 बिलियन डॉलर का फंड।
- ब्रिक्स देशों के नए विकास बैंक के लिये 10 बिलियन डॉलर का फंड।

संभावित प्रश्न

चीन-आधारित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) वैश्वीकरण के उदय के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभर रही है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत पर पड़ने वाले इसके ग्राहकों की चर्चा कीजिये और बताएं कि भारत द्वारा इस परियोजना में शामिल न होने का फैसला कहाँ तक प्रासंगिक है? (200 शब्द)

